

प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग में चर्चा

6 फरवरी, 2015

प्रधानमंत्री ने सहकारितापूर्ण संघवाद पर ज़ोर दिया, विकास के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का समर्थन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। यह प्रधानमंत्री का नीति आयोग का पहला दौरा था।

प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि नीति आयोग का एक उद्देश्य एक ऐसे सशक्त सांस्थानिक तंत्र की स्थापना करना था जिसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था से बाहर की प्रमुख हस्तियां नीति निर्माण में योगदान कर सकें।

चर्चा के मुख्य विषय का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सहकारितापूर्ण संघवाद की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि वे विकास के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को मौजूदा वैश्विक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए तेज़ी से विकास करना चाहिए ताकि जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा हाल में शुरू की गई पहलों का जिक्र किया जिनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण तथा स्वच्छ भारत शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उपस्थित प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच सार्थक चर्चा होने तथा उनसे सुझाव मिलने की उम्मीद है।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पानगड़िया ने भी संक्षिप्त शुरुआती संबोधन दिया।

चर्चा में उपस्थित अर्थशास्त्री थे- श्री विजय केलकर, श्री नितिन देसाई, श्री बिमल जालान, श्री राजीव लाल, श्री आर वैद्यनाथन, श्री सुबीर गोकर्ण, श्री पार्थसारथी शोम, श्री पी. बालकृष्णन, श्री राजीव कुमार, श्री अशोक गुलाटी, श्री मुकेश बूटानी तथा श्री जी.एन. बाजपेयी।

अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार को उच्च वृद्धि दर, अनुमान्य कर व्यवस्था, मौद्रिक सक्षमता तथा त्वरित अवसंरचनात्मक विकास पर बल देना चाहिए। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी काफी सुझाव दिए गए।

बैठक में नीति आयोग के सदस्य श्री बिबेक देबरॉय और डॉ. वी. के. सारस्वत के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद थीं। मंत्रिमंडल सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिवगण, मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।